



IAS, IPS, IFOS पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्तिलाभों से संबंधित संशोधित नयिम

प्रलिस के लयि:

अखलि भारतीय सेवारूँ (AIS). कार्मकि और प्रशकिषण वभिग (DoPT), सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, सविलि सेवा नयिम, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ संशोधन नयिम 2023

मेन्स के लयि:

भारतीय प्रशासनकि सेवा (Cadre) नयिम 1954, अखलि भारतीय सेवारूँ (AIS), AIS अधिकारी की प्रतनियुक्ति, AIS अधिकारियों की संघीय प्रकृति, **केंद्र राज्य संबंध, लोकतंत्र में सविलि सेवाओं की भूमिका**

चर्चा में क्योँ ?

केंद्र सरकार ने IAS, IPS (भारतीय पुलसि सेवा) और IFO (भारतीय वन सेवा) पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्तिलाभों से संबंधित अखलि भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ) नयिम 1958 में संशोधन कयि है।

- नयिम 1958 को कार्मकि और प्रशकिषण वभिग (DOPT) द्वारा नयिम 2023 में संशोधित कयि गया था।
- यह मुख्य रूप से सेवानिवृत्त खुफयि या सुरक्षा से संबंधित संगठनों पर केंद्रति है।

नयिम 2023 द्वारा परविरतन:

- केंद्र सरकार स्वयं IAS, IPS और IFos के वरिद्ध कार्रवाई करने तथाराज्य सरकार के संदर्भ के बनिा भी उनकी पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार रखती है यद्वि गंभीर कदाचार या अपराध के लयि दोषी पाए जाते हैं।
- संशोधित नयिम दर्शाते हैं कि पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का नरिणय "अंतमि होगा"।
 - इन जोड़े गए नयिमों में 'गंभीर कदाचार' में आधिकारकि गोपनीयता अधनियिम में उल्लिखित कसिँ दस्तावेज़ या जानकारी का संचार या प्रकटीकरण शामिल है तथा 'गंभीर अपराध' में आधिकारकि गोपनीयता अधनियिम के तहत अपराध से संबंधित कोई भी अपराध शामिल है।
 - अखलि भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ) नयिम, 1958 में पहले नयिम 3(3) में कहा गया था कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ पर पेंशन या उसके कसिँ भी हसिसे को रोक या वापस ले सकती है।
- खुफयि या सुरक्षा-संबंधी संगठनों के सदस्य, जनिहोंने ऐसी क्षमताओं में सेवा की है, अपने संबंधित संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी प्राप्त कयि बनिा कोई लेख नहीं लिखेंगे या प्रकाशित करेंगे।

नयिमों में बदलाव का असर:

- गंभीर कदाचार के दोषी या अदालत द्वारा गंभीर अपराध के दोषी पाए गए पेंशनभोगी के खलिाफ कार्रवाई करने के लयिकेंद्र को राज्य सरकार के संदर्भ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
 - ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ के बनिा भी केंद्र सरकार कार्रवाई की प्रकयिा शुरू कर सकती है।
- सुरक्षा और खुफयि संगठनों के अधिकारियों द्वारा मीडियि में संवेदनशील जानकारी प्रदान करने तथा कतिाबों में उनके बारे में लिखने पर संबंधित सुरक्षा एवं खुफयि संगठनों के अधिकारियों के खलिाफ कार्रवाई की जाएगी।
- प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नयित्रण को कमज़ोर कर देगा।
- यह प्रभावी शासन को बाधित करेगा और परहिर्य कानूनी तथा प्रशासनकि विवाद पैदा करेगा। क्योँकि संशोधित नयिम केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारियों के खलिाफ कार्रवाई करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान करेंगे।

अखलि भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ) नयिम, 1958

- अखलि भारतीय सेवा अधनियिम, 1951 की धारा 3 (1951 का 61) संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श के बाद ऐसे नयिम बनाने के लयि केंद्र

सरकार को अधिकार देता है।

- यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 29 अक्टूबर, 1951 को या उसके बाद सेवा से सेवानवृत्त हुए थे।
- यह सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होता है जिनमें राज्य सेवाओं से केंद्रीय सेवा में पदोन्नत किया गया था या भारतीय प्रशासनिक सेवा (राज्यों तक वसितार) योजना या भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत सेवा में नियुक्त किया गया था।
- इन नियमों में नहिंति कोई भी बात 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में नियुक्त लोगों पर लागू नहीं होगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. “आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक नरिणायक चालक है”। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (2020)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amended-rules-relating-to-retirement-benefits-of-ias,-ips,-ifos-pensioners>

